शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 29 – 5 फरवरी 2024 मूल्य पांच रूपये

# प्रतिभा सिंह और राजेन्द्र राणा के स्वरों के परिदृश्य में लोकसभा चुनावों में सफलता पर उठने लगे सवाल

- इन्तकाल और तक्सीम से हटकर भी हैं लोगों की समस्याएं
- सुखाश्रय से हटकर दूसरे वर्गों पर कब ध्यान जायेगा

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा मण्डी से लोकसभा सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह ने अभी फिर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सरकार में अनदेखी होने का दुख: सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सरकार के विभिन्न आदारों में समायोजन हेतु मुख्यमंत्री को एक सूची भी सौंपी थी जिस पर अभी

तक कोई अमल नहीं हो पाया है। इसी तरह की चिन्ता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा ने व्यक्त की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी के चुने हुये विधायकों पर कैबिनेट रैंक की ताजपोशीयां पाये गैर विधायक भारी पड़ रहे हैं। राजेंद्र राणा ने तो एक बार फिर मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखकर विभिन्न चुनावी वायदों की याद दिलाई है जो आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा पूछे जायेंगे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने का सवाल पूर्व अध्यक्ष विधायक कुलदीप राठौर भी उठा चुके हैं। यह सभी लोग संगठन से जुड़े हुये लोग हैं और इन्ही के कार्यकाल में कांग्रेस ने उपचुनाव और नगर निगम सोलन तथा पालमपुर के चुनाव कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीते थे।

मुख्यमंत्री सुक्खु भी संगठन से निकले हुये नेता हैं। एनएसयूआई युवा कांग्रेस और फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तक रह चुके हैं। शायद इसी आधार पर वह मुख्यमंत्री के लिए पहली पसन्द बने हैं। जब सुक्खु पार्टी के अध्यक्ष थे तब उनमें और मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह में गहरे मतभेद रहे हैं यह सब जानते हैं। लेकिन स्व. वीरभद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति और जनता में जो अपना एक विशेष स्थान है उस मुकाम तक दूसरे नेताओं को पहुंचने में बड़ा वक्त लगेगा। वीरभद्र के समर्थकों की आज भी एक लम्बी लाईन है और हर नेता को जनता उसी तराजू में तोलकर उसका गुणा – भाग करके आकलन करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खु ने भी गैर विधायकों को कार्यकर्ता होने के नाम पर ही ताजपोशियां दी हैं। लेकिन यह ताजपोशियां पाये हुये नेताओं का अपना जनाधार क्या है यह सवाल संगठन में ही उठाना शुरू हो गया है। इन नेताओं के सहारे क्या लोकसभा की कोई एक सीट जीतने का दावा किया जा सकता यह संगठन के अन्दर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लोकसभा चुनावों के लिये इन्हीं मजबूत बनाये गये नेताओं में से ही उम्मीदवार बनाने का सवाल खड़ा किया जा रहा है। यहां तक चर्चाएं उठनी शुरू हो गयी हैं की मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक कोई मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में तो एक भी सीट विपक्ष को नहीं जाने की स्थिति होनी चाहिये। लेकिन हिमाचल में व्यवहारिक रूप से हालात एकदम इससे उलट बनते जा रहे हैं। प्रदेश का कोई भी छोटा – बड़ा नेता केन्द्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का साहस नहीं कर पा रहा है।

इस समय जनता में जाने के लिए ''सरकार गांव के द्वार'' कार्यक्रम का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसके तहत अब तक जितने भी आयोजन हुये हैं। उनमें राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये गये इन्तकाल और तक्सीम के मामलों के आंकड़ो का ही ब्योरा परोसा जा रहा है। लाभार्थियों के नाम पर आपदा राहत और सुखाश्रय के आंकड़ों से हटकर कोई और उपलब्धि नहीं बताई जा रही है। क्या आज प्रदेश में इनसे हटकर कोई और समस्याएं आम आदमी की नहीं हैं। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उनसे फील्ड में कितने लोगों को लाभ मिला है इसका कोई आंकड़ा जारी नहीं हो पा रहा है। ''सरकार गांव के द्वार'' और स्कूलों द्वारा आयोजित किये जा रहे वार्षिक समारोहों के कार्यक्रमों से हटकर जनता में जाने के लिये और कोई मंच संगठन या सरकार की ओर से अभी तक सामने नहीं आ पाया है। भाजपा द्वारा उठाये जा रहे सवालों का एक ही जवाब दिया जा रहा है कि केन्द्र ने आपदा में प्रदेश की कोई मदद नहीं की है। प्रदेश के भाजपा सांसदों और विधायकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह केन्द्र के सामने प्रदेश की आवाज उठाने के लिये सरकार के साथ खड़े नहीं हुये हैं। लेकिन भाजपा ने इस पर सरकार द्वारा लिये गये कर्ज के जो आंकड़े जारी किये हैं उनका कोई तार्किक जवाब नहीं दिया जा रहा है। यह नहीं बताया जा रहा है कि इस कर्ज को खर्च कहां किया जा रहा है।

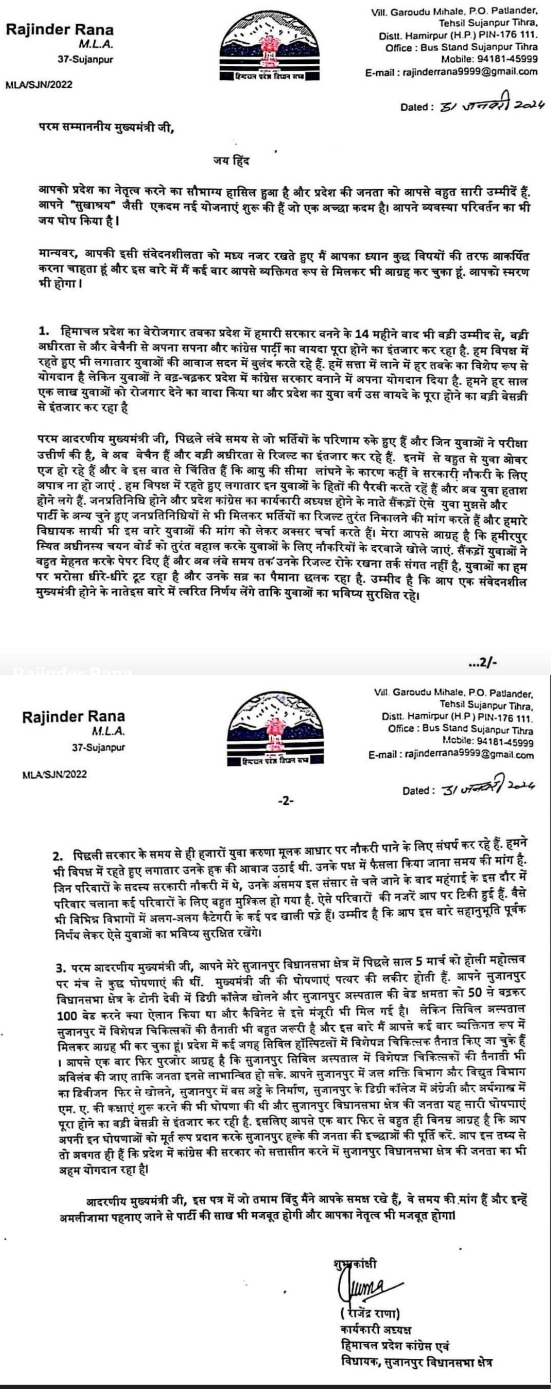

Rajinder Rana
M.L.A.
37-Sujanpur
MLA/SJN/2022

Vill. Garoudu Mihale, P.O. Patlander,
Tehsil Sujanpur Tihra,
Distt. Hamirpur (H.P.) PIN-176 111.
Office : Bus Stand Sujanpur Tihra
Mobile: 94181-45999
E-mail : rajinderrana9999@gmail.com

Dated : 31 जनवरी 2024

परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी,

जय हिंद

आपको प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य हासिल हुआ है और प्रदेश की जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं. आपने "सुखाश्रय" जैसी एकदम नई योजनाएं शुरू की हैं जो एक अच्छा कदम है। आपने व्यवस्था परिवर्तन का भी जय घोष किया है।

मान्यवर, आपकी इसी संवेदनशीलता को मध्य नजर रखते हुए मैं आपका ध्यान कुछ विषयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और इस बारे में मैं कई बार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आग्रह कर चुका हूं. आपको स्मरण भी होगा।

1. हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार तबका प्रदेश में हमारी सरकार बनने के 14 महीने बाद भी बड़ी उम्मीद से, बड़ी अधीरता से और बेचैनी से अपना सपना और कांग्रेस पार्टी का वायदा पूरा होने का इंतजार कर रहा है. हम विपक्ष में रहते हुए भी लगातार युवाओं की आवाज सदन में बुलंद करते रहे हैं. हमें सत्ता में लाने में हर तबके का विशेष रूप से योगदान है लेकिन युवाओं ने बढ़-चढ़कर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है. हमने हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और प्रदेश का युवा वर्ग उस वायदे के पूरा होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है

परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पिछले लंबे समय से जो भर्तियों के परिणाम रूके हुए हैं और जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब बेचैन हैं और बड़ी अधीरता से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. इनमें से बहुत से युवा ओवर एज हो रहे हैं और वे इस बात से चिंतित हैं कि आयु की सीमा लांघने के कारण कहीं वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र ना हो जाएं. हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इन युवाओं के हितों की पैरवी करते रहें हैं और अब युवा हताश होने लगे हैं. जनप्रतिनिधि होने और प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सैंकड़ों ऐसे युवा मुझसे और पार्टी के अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर भर्तियों का रिजल्ट तुरंत निकालने की मांग करते हैं और हमारे विधायक साथी भी इस बारे युवाओं की मांग को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हमीरपुर स्थित अधीनस्थ चयन बोर्ड को तुरंत बहाल करके युवाओं के लिए नौकरियों के दरवाजे खोले जाएं. सैंकड़ों युवाओं ने बहुत मेहनत करके पेपर दिए हैं और अब लंबे समय तक उनके रिजल्ट रोके रखना तर्क संगत नहीं है, युवाओं का हम पर भरोसा धीरे-धीरे टूट रहा है और उनके सब्र का पैमाना छलक रहा है. उम्मीद है कि आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नातेइस बारे में त्वरित निर्णय लेंगे ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

...2/-

Rajinder Rana
M.L.A.
37-Sujanpur
MLA/SJN/2022

Vill. Garoudu Mihale, P.O. Patlander,
Tehsil Sujanpur Tihra,
Distt. Hamirpur (H.P.) PIN-176 111.
Office : Bus Stand Sujanpur Tihra
Mobile: 94181-45999
E-mail : rajinderrana9999@gmail.com

Dated : 31 जनवरी 2024

-2-

2. पिछली सरकार के समय से ही हजारों युवा करुणा मूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हमने भी विपक्ष में रहते हुए लगातार उनके हक की आवाज उठाई थी. उनके पक्ष में फैसला किया जाना समय की मांग है. जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में थे, उनके असमय इस संसार से चले जाने के बाद महंगाई के इस दौर में परिवार चलाना कई परिवारों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है. ऐसे परिवारों की नजरें आप पर टिकी हुई हैं. वैसे भी विभिन्न विभागों में अलग-अलग कैटेगरी के कई पद खाली पड़े हैं। उम्मीद है कि आप इस बारे सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेकर ऐसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।

3. परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल 5 मार्च को होली महोत्सव पर मंच से कुछ घोषणाएं की थीं. मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं पत्थर की लकीर होती हैं. आपने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टोनी देवी में डिग्री कॉलेज खोलने और सुजानपुर अस्पताल की बेड क्षमता को 50 से बढ़कर 100 बेड करने क्या ऐलान किया था और कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन सिविल अस्पताल सुजानपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी बहुत जरूरी है और इस बारे में आपसे कई बार व्यक्तिगत रूप में मिलकर आग्रह भी कर चुका हूं। प्रदेश में कई जगह सिविल हॉस्पिटलों में विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं। आपसे एक बार फिर पुरजोर आग्रह है कि सुजानपुर सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी अविलंब की जाए ताकि जनता इनसे लाभान्वित हो सके. आपने सुजानपुर में जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग का डिवीजन फिर से खोलने, सुजानपुर में बस अड्डे के निर्माण, सुजानपुर के डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में एम. ए. की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की थी और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता यह सारी घोषणाएं पूरा होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसलिए आपसे एक बार फिर से बहुत ही विनम्र आग्रह है कि आप अपनी इन घोषणाओं को मूर्त रूप प्रदान करके सुजानपुर हल्के की जनता की इच्छाओं की पूर्ति करें. आप इस तथ्य से तो अवगत ही हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्तासीन करने में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी अहम योगदान रहा है।

आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस पत्र में जो तमाम बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, वे समय की मांग हैं और इन्हें अमलीजामा पहनाए जाने से पार्टी की साख भी मजबूत होगी और आपका नेतृत्व भी मजबूत होगा।

शुभकांक्षी

(राजेंद्र राणा)
कार्यकारी अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस एवं
विधायक, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र

# राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

**शिमला/शैल।** शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के पथ पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। सम्पूर्ण राष्ट्र कृतज्ञ भाव से आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश वर्तमान में और अधिक प्रासंगिक हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हो गया और अहिंसा का मार्ग चुनते हुए समर्पित प्रयासों से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रपिता के आदर्शो से प्रेरणा लेने और गांधी जी के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने का आहवान करते हुए कहा कि यही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखा गया तथा देशभक्ति के गीत एवं भजन भी प्रस्तुत किए।

राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविन्द्र गोमा, सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, वन विकास निगम के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, उपमहापौर उमा कौशल, उपायुक्त आदित्य नेगी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार, नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेन्द्र कुमार अत्री, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

# मुख्यमंत्री ने वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को मुख्य हाइड्रोग्राफर बनने पर बधाई दी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के शाहपुर क्षेत्र के मूल निवासी वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को भारत

सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक (हाइड्रोग्राफर) का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है।

भारतीय नौ सेना का जल सर्वेक्षण विभाग, जल सर्वेक्षण एवं नौपरिवहन चार्ट के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लोचन सिंह पठानिया नौ सेना के जल सर्वेक्षण जहाज आईएनएस 'दर्शक' और 'संधायक' को भी कमांड कर चुके हैं। अपने तीन दशकों से अधिक के सेवा काल में उन्होंने जल सर्वेक्षण से संबंधित कार्यो से अपनी विशेष पहचान बनाई है।

मुख्य जल सर्वेक्षक के रूप में उनके शानदार कार्यकाल की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को उनकी उपलब्धि पर गर्व है और वह भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छुक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 'वीरभूमि' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी राज्य के वीर सपूत अपनी वीरता और साहस के

# नशीले पदार्थों पर रोकथाम के लिए सभी हितधारक आपसी समन्वय से करें कार्य:मुख्य सचिव

**शिमला/शैल।** मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशामुक्त भारत अभियान के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थो, दवाओं इत्यादि की तस्करी के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। नशीली दवाओं के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कारवाई सुनिश्चित की जा रही है। टोल फ्री ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन नंबर 1908 आरम्भ किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को नशीली दवाओं के तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा नशा सेवन में संलिप्त युवाओं और उनके माता-पिता को परामर्श प्रदान करना है। नशे की आपूर्ति से जुड़े लोगों के बारे में सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है।

उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है जिससे मानसिक सामाजिक व अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थो के सेवन पर रोक लगाने व नशा निवारण के लिए शिक्षा, जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास, क्षमता निर्माण के लिए मानव संसाधन का विकास और नशे में संलिप्त युवाओं से भेदभाव को कम करने की रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में सभी हितधारकों को जिम्मेदारियां साझा कर आपसी सहयोग की भावना से काम करना चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस, दिल्ली अरुल वार्मा ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी रणनीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नशे में संलिप्त व्यक्तियों तक पहुंचने और नशीले पदार्थो की मांग को कम करने में सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों में किशोरों और युवाओं में नशीली दवाओं के उपयोग की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय- सहकर्मी नेतृत्व आधारित हस्तक्षेप सहित अन्य कदम उठाये जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षकों के बीच जिम्मेदारी की भावना विकसित करना नितांत आवश्यक है ताकि प्रारम्भिक अवस्था में रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन स्कूली विद्यार्थियों को नशे के सेवन की लत हो जाती है, वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और शैक्षणिक संस्थान भी छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उनको उचित परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मानक प्रक्रियाओं और श्रेष्ठ प्रथाओं को स्थापित करने के लिए उपचार और पुनर्वास स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे पुनर्वास केंद्रों को कौशल विकास के साथ जोड़ने की भी आवश्यकता है। उपचाराधीन व्यक्तियों को शीघ्र पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह कदम चिकित्सीय होने के साथ-साथ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी भी है।

अपराध की रोकथाम के उपाय के रूप में, मादक द्रव्यों के आदी लोगों को चिन्हित करने और उन्हें उपचार के लिए संगठनों के पास भेजने की आवश्यकता है और यदि वे ड्रग्स बेचते पाये जाते हैं तो आवश्यक कानूनी कदम सुनिश्चित की जानी चाहिए। नशीले पदार्थो की आपूर्ति पर रोक लगाने तथा नशे में संलिप्तों के कल्याण के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना समाज में नशे की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए कई नवीन प्रयास किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए पहला कदम दवाओं की आपूर्ति में लगाम कसना है। मादक द्रव्य प्रवर्तन से संबंधित सभी प्रवर्तन एजेंसियां आपूर्ति लाईनों को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम सुधा देवी ने कहा कि सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि नशे के आदी लोगों द्वारा इनहेलेंट, अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड पदार्थो जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थो का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर ने कार्यशाला में विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# पांगी किलाड़ में 1 फीट ताजा हिमपात मुछ गांव में छाया हिमखंड का खत्तरा

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में लगातार बर्फबारी के कारण मुख्यालय किलाड़ में एक फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। वहीं उंचाई वाले क्षेत्रों में दो फीट हिमपात हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी किसानों व बागवानों के लिए संजीवनी बनी हुई है। वहीं उधर जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। घाटी के मुख्यालय किलाड़ में 1 फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। वहीं उपरले क्षेत्रों में दो फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। घाटी का शेष दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। मौजूदा समय में घाटी के 19 पंचायतों के लोग घरों में कैद हो गई है। बिजली व्यवस्था समते सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप पड़े हुए है। हिमपात के कारण पांगी घाटी में वाहनों की रफ्तार थम गई है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कुमार, परमार, सुराल, चसग, हिलूटवान, शुण समेत करयूनी सेरी में दो फीट तक ताजा हिमपात हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत पेश आयी। बर्फबारी की वजह से पांगी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। घाटी के 15 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़ गये हैं। पांगी के पंचायत रेई, थांथल, शौर, कुमार, परमार व प्रेग्रा की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली गुल होने के चलते इन पंचायतों के दायरे में आने वाले गांव वालों को अगले कुछ दिनों तक सर्द रातें अंधेरे में काटनी पड़ सकती है। तहसीलदार पांगी शांता कुमार ने बताया कि घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत दी गई है।

पांगी घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 19 पंचायतों के प्रधानों से संपर्क किया जा रहा है। प्रशासन से आपदा के दौरान हर पंचायत में स्थानीय युवाओं की टीम बनाई हुई है। जोकि गांव में बर्फबारी के कारण आयी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वहीं पांगी से शेष दुनिया का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है मौजूदा समय पांगी से बाहर आने से रास्ते केवल दो है। जिनमें वाया कुल्लू मनाली लाहुल के राहूली नामक स्थान पर भारी भूस्खलन के चलते बंद पड़ा हुआ है। वहीं वाया जम्मू कश्मीर से भारी बर्फबारी के कारण बंद हुआ है।

पांगी घाटी के ग्राम पंचायत

सेचू के मुर्छ गांव पर एक बार फिर हिमखंड का खत्तरा मंडराता हुआ है। क्योंकि मूर्छ गांव में दो बार हिमखंड जैसी आपदा आ चुकी है। वर्ष 2020 में मूर्छ गांव में करीब 6 फीट बर्फ हुई थी। इस दौरान गांव में आये हिमखंड ने 5 परिवारों को बेघर कर दिया था। गांव 12 हजार की ऊंचाई पर पर है। ऐसे में यहां पर अभी तक तीन फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। मुर्छ गांव में करीब 35 परिवार रहते है। गांव के पंचायत तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। हालांकि पांगी प्रशासन से गांव की स्थिति जानने के लिए वार्ड सदस्य से संपर्क किया जा रहा है।

# प्रदेश में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठा रही प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'विश्व वेटलैंड दिवस' के उपलक्ष्य पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के दृष्टिगत वेटलैंड के संरक्षण का आहवान किया है। यह आर्द्र भूमि क्षेत्र इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से हिमाचल में स्थित रामसर स्थलों एवं अन्य वेटलैंड क्षेत्रों के संरक्षण के लिये सक्रिय सहयोग का भी आग्रह किया।

इस वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस की विषय-वस्तु 'आर्द्र भूमि और मानव कल्याण' रखी गई है। इस दिवस का आयोजन 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर आयोजित सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित रामसर समझौते के उपलक्ष्य में वर्ष 1997 से किया जा रहा है।

वेटलैंड समाज को पर्यावरण संतुलन प्रदान करते हैं। इनमें ताजा जल, पानी में से नुकसानदायक अपशिष्ट को छानकर इसे पीने के लिए शुद्ध बनाते हैं। इसके साथ ही यह खाद्य पदार्थों के बेहतर स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं। विषम मौसमी घटनाओं के दौरान भी वेटलैंड अत्याधिक जल प्रवाहन तथा सूखे जैसे जोखिमों को कम करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही असंख्य लोगों के लिए जीवनयापन का स्रोत भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार सहित स्थानीय समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विविध वेटलैंड फैले हुए हैं। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों की आजीविका की पूर्ति के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य एवं पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में प्रदेश में स्थित पौंग बांध, रेणुका और चंद्रताल झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रिवालसर और खजियार झील को राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इन स्थलों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरण के माध्यम से इस दिशा में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। वेटलैंड के संरक्षण, प्रबंधन, सुरक्षा और वेटलैंड सम्बंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय वेटलैंड समितियां भी गठित की गई हैं। ईको-क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को इससे जोड़ा गया है और सामुदायिक स्तर पर वेटलैंड बचाव अभियान के माध्यम से इनके बारे में जागरूकता लायी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा वन, शिक्षा, पर्यटन, मत्स्य पालन विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर गोबिंद सागर झील, पौंग बांध एवं रेणुका वेटलैंड सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मण्डी जिला के रिवालसर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी भाग लेंगे। इस दौरान सप्ताह भर चलने वाले स्वच्छता एवं जागरूकता अभियानों के अतिरिक्त पंचायत व स्कूलों के स्तर पर इन स्थलों के महत्व पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिताएं, संवाद और व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे।

# प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा केन्द्रीय अन्तरिम बजट:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार का अन्तरिम बजट देशवासियों और हिमाचल की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है और यह प्रदेशवासियों को निराश करने वाला बजट है। इसे पिछले बजट का दोहराव करार देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम बजट भाषण में कोई भी नई बात नहीं कही गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत बरसात में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेशवासियों को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी लेकिन इसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि रेल नेटर्वक के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हिमाचल का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की बात कही गई है किंतु इसके लिये कोई स्पष्ट रोडमैप का उल्लेख उनके अभिभाषण में नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए कर में कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों में वृद्धि की गई है और आमजन के लिये डीजल तथा पैट्रोल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाये इस बजट में केवल पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.8 लाख करोड़ तक पहुंचने के बावजूद आयकर तथा अन्य करों में कोई भी अतिरिक्त रियायत नहीं दी गई है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जहां मेट्रो रेल शुरू नहीं की जा सकती, वहां के लिए किसी भी तीव्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किसी नई पहल का जिक्र नहीं किया गया है।

# आगामी बजट में दिखेगी आत्मनिर्भर एवं समृद्ध हिमाचल की झलक: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल के कार्यक्रम चौपाल में भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा तीव्र विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का आगामी बजट भी इन्हीं बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की भी झलक देखने को मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गो के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़संकल्प है। उन्होंने कहा कि अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल किया गया है। इससे लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों का सेवानिवृति के उपरान्त सम्मानजनक जीवन-यापन सुनिश्चित हुआ है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल में सभी मौसमों के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बर्फीली पहाडियां, हरे-भरे मैदान, यहां के जलाशय तथा सघन वन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र को विविधता प्रदान करते हैं। यह प्रत्येक आयु वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में ढांचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार करने के साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय को हैलीपोर्ट से जोड़ कर हवाई सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को आवागमन की तीव्र एवं सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष आपदा के दौरान चन्द्रताल की बर्फीली चोटियों सहित अन्य क्षेत्रों में फंसे हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, जोकि पर्यटन एवं पर्यटकों की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के उपरान्त रिकार्ड समय में सामान्य व्यवस्था बहाल करते हुए प्रदेश सरकार ने सुशासन का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल के.एस. बांशटू भी उपस्थित थे।

# दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र ढगवार स्थापित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा एनडीडीबी:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र की क्षमता शुरूआत में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में 225 करोड़ के निवेश से निर्माण कार्य किया जाएगा। संयंत्र का उद्देश्य दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फलेवर्ड मिल्क, खोया तथा मौज़रेला चीज़ जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के आरम्भ होने से दुग्ध उत्पादकों के जीवन में खुशहाली आएगी तथा प्रदेश की समग्र प्रगति में भी योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा तथा ऊना जिले के किसानों से सीधे तौर पर दूध खरीद कर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने दूध प्रापण में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को उनकी मेहनत के उचित दाम मिलेगें।

उन्होंने कहा कि दूध प्रापण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 43 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का प्रावधान किया गया है। संयंत्र को संचालित करने के उद्देश्य से प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल किसान कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें दूसरे चरण के तहत ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम तथा विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा हाल ही में दूध प्रापण दर में सीधे 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर, यह दर 32 रुपये से बढ़कर 38 रुपये की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है तथा भविष्य में नयी योजनाएं आरम्भ की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 95 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के बिना आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है।

# क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 72 करोड़ रुपये की राशि जारी:विक्रमादित्य

**शिमला/शैल।** लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में गत बरसात के दौरान भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी तथा इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मण्डलों को इस

आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार व मरम्मत के लिए एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के तहत अभी तक 259 करोड़ रुपये की निधि जारी की जा चुकी है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त मुख्य सड़कें रिकॉर्ड समय में बहाल की गई। विशेष तौर पर विभाग ने सेब बहुल क्षेत्रों में सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जिससे सेब उत्पादकों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विकास तथा सड़कों के रख-रखाव के लिए विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।

# राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ने के लिए 29 फरवरी तक बढ़ाई

**शिमला/शैल।** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। इसके लिए ईकेवाईसी की तिथि बढ़ाकर 29 फरवरी, 2024 की गई है। इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। किसी कारणवश पंजीकरण न कर सकने वाले उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथि तक ईकेवाईसी प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें। ऐसा न करने पर राशन कार्ड को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने पर ही पुन: शुरू किया जाएगा।

लाभार्थी अपना सक्रिय मोबाइल नम्बर विभाग से साझा कर खाद्यान्नों से सम्बंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे पारदर्शिता पोर्टल अथवा विभागीय बैवसाइट पर स्वयं भी अपना नम्बर अपडेट कर सकते हैं।

जीवन का रास्ता बना बनाया नही मिलता, इसे स्वंय बनाना पड़ता है।
जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है।

..... स्वामी विवेकानन्द

## सम्पादकीय

# क्या मोदी ''राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा'' के बाद भी शंकित है

राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद जो कुछ बिहार झारखण्ड और चण्डीगढ़ में घटा है उसने संवेदनशील नागरिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह सवाल उठ है कि जिस तरह से चण्डीगढ़ के मेयर का चुनाव भाजपा ने जीता है क्या उसी तरह का आचरण लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? यह आशंका इसलिये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ई.वी.एम. पर हर चुनाव के बाद उठते सवाल आज वकीलों के आन्दोलन तक पहुंच गये है। उन्नीस लाख के लगभग ई.वी.एम. मशीने गायब होने का खुलासा आर.टी.आई. के माध्यम से सामने आ चुका है। ई.वी.एम. हैक हो सकती है इसका प्रमाण दिल्ली विधानसभा के पटल पर किया जा चुका है। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय पर इस सबका कोई असर नही हो रहा है। संभव है कि इस बार ई.वी.एम. के खिलाफ उठा आन्दोलन बहुत दूर तक जाये। इस समय महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी पर उठते सवालों का कोई जवाब सरकार नही दे रही है। देश की आर्थिकी पर परोसे जा रहे दावों और आंकड़ों पर सवाल उठाना संभव नही रह गया है। जी.डी.पी. की बढ़ौतरी स्थिर मूल्य पर है या चालू कीमतों पर इसका कोई जवाब सरकार के पास नही है। सारे आंकड़ें बढ़ते कर्ज पर आधारित हैं। जी.डी. पी. का 80 प्रतिशत कर्ज है और यह कर्ज चुकाने के बाद क्या बचेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इतने कर्ज के बाद भी जब देश की 80 करोड़ जनता सरकार के सस्ते राशन के सहारे जिन्दा है तो इसी से प्रति व्यक्ति की बढ़ती आय का सच सामने आ जाता है। यह चित्र एक व्यवहारिक सच है जो हर चुनाव के बाद और नंगा होकर आम आदमी के सामने आता जा रहा है। यही सच आम आदमी की चिन्ता और चिन्तन का केंद्र बनता जा रहा है।

लेकिन यह भी एक प्रमाणित सच है कि रात चाहे कितनी भी काली और लम्बी क्यों न हो पर सवेरा आकर ही रहता है। इस समय सारे गंभीर प्रश्नों से ध्यान हटाने का जो प्रयोग धर्म और जातियों में आपसी टकराव खड़ा करके किया जा रहा था उसका एक चरम अभी राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में सामने आ चुका है। इस आयोजन पर शंकराचार्यो से लेकर अन्य विश्लेषको ने जो सवाल उठाये हैं उससे शायद सत्ता को कुछ झटका लगा है। इसलिये इस आयोजन के बाद राहुल गांधी के न्याय यात्रा को असफल करने के लिये हर राज्य में अड़चने पैदा करने का प्रयास किया गया है। इसी के लिये ''इण्डिया'' गठबन्धन को तोड़ने के सारे प्रयास शुरू हो गये हैं। जिस तरह से गठबन्धन के बड़े घटक दल अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस को सीटे देने के लिये तैयार नही हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि चुनावों से पहले ही यह गठबन्धन दम तोड़ देगा। सभी दल अलग-अलग चुनाव लड़ने की बाध्यता पर आ जायेंगे।

राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन ने हर दल को प्रभावित किया है। बल्कि हर दल में वह लोग स्पष्ट रूप से चिन्हित हो गये हैं जो धर्म की राजनीति में संघ भाजपा के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। ऐसे में यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि जो राजनीतिक लोग या दल धर्म और राजनीति में ईमानदारी से अन्तर मानते हैं उन्हें बड़े जोर से यह कहना पड़ेगा की राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ है वह शुद्ध रूप से संघ भाजपा का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। इस आयोजन के बाद भाजपा के ही अन्दर उठने वाले सवालों को लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर चुप करवाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस आयोजन के बाद जो कुछ बिहार, झारखण्ड और चण्डीगढ़ में घटा है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि मोदी अभी भी शंकित हैं कि क्या अकेला राम मन्दिर ही उनको सफलता दिला पायेगा? इसी शंका ने उनको ''इण्डिया'' को तोड़ने के प्रयासों में लगा दिया है। ''इण्डिया'' में नीतीश कुमार, ममता बैनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल की सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह का आचरण सामने आ रहा है उसका भाजपा और कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर अगले अंक में आकलन किया जायेगा। लेकिन जो कुछ मोदी ने किया है वहां निश्चित रूप से उनके डर का ही प्रमाण है।

# राष्ट्रीय आस्था का मापदंड धार्मिक या व्यक्तिगत पहचान नहीं हो सकता

गौतम चौधरी

अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के दुर्गम इलाके में, एक ध्वस्त सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को बचाने में जिस प्रकार देश के हर वर्ग का समर्थन और सहयोग मिला उससे एक बार फिर साबित हो गया कि हमारी एकता अद्भुत है। इस घटना के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे देश की एकजुटता और अटूट समर्पण का असाधारण प्रदर्शन सामने आया। दुनिया ने देखा कि उस चुनौतियों का सामना केवल तकनीक और विशेषज्ञता के बल से नहीं की गयी, अपितु विविध कार्यबल का लचीलापन, वीरता और एकता ने भी समान भूमिका निभाई। उस कठिन घड़ी में हमारे देश के मुसलमान सदा की तरह हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे थे। अधिकतर स्थानों पर तो वे नायक की भूमिका में दिखे। उन नायकों में कई गुमनाम हैं लेकिन उन्होंने वही किया जो एक देश के नागरिक को अपने भाई, बंधु-बांधवों के लिए करना चाहिए।

यह कठिन अभियान बीते वर्ष 12 नवंबर को शुरू हुआ, जब भूस्खलन के कारण श्रमिक सुरंग के अंधेरे दायरे में फंस गए थे। कई असफलताओं और उन्नत मशीनों की विफलता के बाद भी हमारे विशेषज्ञ लगातार प्रयास करते रहे। विशेषज्ञों के समूह ने हार नहीं मानी। वे लगातार प्रयास करते रहे और पूरे देश की आशा का केन्द्र बने रहे। इस दृढ़ संकल्पित समूह में मुन्ना कुरैशी, फिरोज अंसारी, नसीम अंसारी, इरशाद सैफी, राशिद अंसारी, वकील अहमद, नासिर इदिरेसी, जतिन लोधी और अंकुर जयवाल जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस टीम ने न केवल अपनी सिद्धस्तता साबित की अपितु राष्ट्रीय एकता का भी परिचय दिया। विशेषज्ञों की इस टीम ने यह भी साबित कर दिया कि जब हमारे ऊपर चुनौती आती है तो हम अपने आपसी गतिरोध को खत्म कर पहले उस चुनौतियों का सामना करते हैं और उसमें हम सब एक हो जाते हैं। और जब एक होकर उस चुनौती का सामना करते हैं तो अंततः जीत हमारी ही होती है।

उस घटना के दौरान बचाव अभियान में मुस्लिम कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिबद्धता ने बाधाओं को पार करते हुए, अपने गैर-मुस्लिम समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इन व्यक्तियों ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की, जो भारत की विविधता में एकता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री के एकता के आहवान की भावना से प्रेरित होकर, असंभव कार्य वास्तविकता में बदल गया। विशेष रूप से, इन नायकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पसमांदा मुस्लिम समुदाय (एक समूह जिसे अक्सर अशरफ केंद्रित राजनीति द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है।) का था। जब सुरंग में फंसे श्रमिकों का परिवार प्रत्याशा में था, ये लोग उत्सुकता से अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी समय इन नायकों के समूह ने प्राकृतिक और दैवीय बाधाओं को पार कर अपने साथियों को टनल से बाहर निकाल लिया। इसमें विशेषज्ञों की जान भी जा सकती थी लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इसमें कौन लोग फंसे हैं। उन्हें तो बस यही पता था कि अंदर फंसे हुए श्रमिक हमारे अपने हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर टनल से बाहर निकालना है। यह वर्तमान दौर के एकता और संवेत प्रयास का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है।

इस बचाव के मद्देनजर, मुसलमानों, विशेषकर पसमांदा मुसलमानों के निर्विवाद योगदान को पहचानना जरूरी है, जो इस राष्ट्र की रीढ़ हैं, जिनकी भक्ति, साहस और प्रतिकूल परिस्थितियों में एकता पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती है। आने वाले समय में यह उन लोगों के लिए भी एक सीख होगी जो नफरत फैलाने में माहिर हैं। उन्हें चुप कराने में भी हमें मदद मिलेगी। यही नहीं यह उन नासमझ लोगों के लिए भी बड़ा उदाहरण है, जो मुसलमानों से नाहक देशभक्ति का प्रमाणपत्र मागते फिरते हैं। यह सबको समझ लेना होगा कि आस्था के आधार पर किसी की राष्ट्रीय पहचना तय नहीं हो सकती है। आस्था के आधार पर किसी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी तय नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अगला किसी धर्म या जाति का है। हमें तो यही समझना होगा कि अगला हमारा भाई है, जाचे उसकी जाति और धार्मिक आस्था कुछ भी हो। भारत पर धार्मिक असहिष्णुता का आरोप लगाने वाले और विरोधी षडयंत्र में शामिल उन तमाम लोगों को उत्तराखंड सुरंग बचाव दल ने एक बार फिर से चुप करा दिया है।

# प्रदेश में पहली बार किया जा रहा इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का आयोजन

## इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों से प्रदेश सरकार कर रही राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा

राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं और एक ऐसी ही अनूठी पहल है प्रदेश भर में इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का आयोजन। पहली बार 30 और 31 अक्तूबर, 2023 को आयोजित की गयी इन इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का उद्देश्य लंबित इंतकाल और तकसीम के मामलों का मौके पर ही निपटारा कर आमजन को लाभान्वित करना है। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर इस तरह की राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं और यह अदालतें उन लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुई है, जो राजस्व सम्बंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्व कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे थे। इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अक्तूबर, 2023 से अब तक सरकार द्वारा आयोजित चार इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों में रिकॉर्ड 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम के लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा चुका है। इस नवीन पहल से समाज के सभी वर्गों से भरपूर समर्थन मिल रहा है क्योंकि उनके लंबित मामलों का घर-द्वार पर ही समाधान हो रहा है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत हो रही है। इन लोक अदालतों को मिल रहे समर्थन का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि अकेले जनवरी, 2024 में 23,159 इंतकाल व 1,958 तकसीम सम्बंधी मामलों का निपटारा किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए भविष्य में भी विभिन्न नयी योजनाओं को आरम्भ किया जाएगा। ''पहली बार, लंबित राजस्व मामलों का समाधान करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी पहली अदालत अक्तूबर, 2023 में आयोजित की गयी थी और इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन अदालतों का संचालन प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में किया जाएगा।''

आम जनता से मिल रहे समर्थन और लंबित मामलों के समाधान की दर को देखते हुए इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

# अंतरिम बजट 2024–25 की मुख्य बातें

**शिमला।** वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में अंतरिम बजट 2024 – 25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सामाजिक न्याय

चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस।

'गरीब कल्याण, देश का कल्याण'

पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की।

पीएम – जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।

पीएम – स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।

पीएम – जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर।

पीएम – विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड – टू – एंड मदद।

'अन्नदाता' का कल्ध्याण

पीएम – किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

पीएम – फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई।

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई – नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद – फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध।

नारी शक्ति पर जोर

30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।

उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा।

स्टेम पाठयक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

पीएम – आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम – आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा।

अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।

छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और निशुल्क बिजली

छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व – सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है।

आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार

50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप – टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी।

रेलवे

लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।

ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा

पत्तन संपर्कता गलियारा

अधिक यातायात वाले गलियारा

40,000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी।

517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं।

देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए।

हरित ऊर्जा

वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।

परिवहन के लिए कम्प्रस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र

राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।

इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा।

निवेश

वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है।

'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।

संशोधित अनुमान (आरई) 2023 – 24

उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है जिसमें से कर प्राप्ति 23. 24 लाख करोड़ रुपए है।

कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए है।

30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2023 – 24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2024 – 25

उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी।

वर्ष 2024 – 25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

वर्ष 2024 – 25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

प्रत्यक्ष कर

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया

पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी

सरकार करदाता सेवाओं में लाएगी सुधार

वित्त वर्ष 2009 – 10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा

वित्त वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा

इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ

सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढाया गया

आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया

अप्रत्यक्ष कर

वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बकरार रखने का प्रस्ताव किया

जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया

इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ

जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ

राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित) जीएसटी से पहले की अवधि (2012 – 13 से 2015 – 16) के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017 – 18 से 2022 – 23) के दौरान 1.22 हो गया

उद्योग जगत के 94 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है

जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्तिसंगत बनी

जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ

लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा

पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास

वित्त वर्ष 2013 – 14 में जहां 2. 2 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं।

खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया

पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया

वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई

विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत रखी गई

करदाता सेवाओं की उपलब्धियां

कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय – सीमा 2013 – 14 के 93 दिन से घटकर दस दिन रह गई

बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरूआत की गई

रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया

सीमा शुल्क सुधारों से आयतित माल छोड़ने के समय में आई कमी

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47 प्रतिशत घटकर 71 घंटे रह गया

एयर कार्गो परिसरों में यह 28 प्रतिशत घटकर 44 घंटे रह गया

समुद्री बंदरगाहों पर 27 प्रतिशत घटकर 85 घंटे रह गया

अर्थव्यवस्था – तब और अब

वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की जरूरत थी:

निवेश आकर्षित करना

बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना

लोगों में उम्मीद जगाना

सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की मजबूत भावना के साथ सफल रही

''अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहां थे और अब कहां है'' वित्त मंत्री

सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक श्वेत – पत्र रखेगी

# मेरा युवा भारत (माय भारत) पोर्टल पर तीन महीनों में पंजीकरण करने वाले युवाओं की संख्या 1.45 करोड़ के पार

**शिमला।** मेरा युवा भारत (माय भारत) पोर्टल ने 31 जनवरी 2024 तक 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरणों के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ऐसा इस पोर्टल के उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के कारण संभव हो सका है जो कुछ ही मिनटों में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर देता है। यह पोर्टल पहले से ही देश के युवाओं को रचनात्मक और परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए संघटित किए जाने को प्रभावित कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी 31 अक्तूबर 2023 को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में देश के युवाओं के लिए 'मेरा युवा भारत (माय भारत)' मंच का शुभारंभ किया था। माय भारत पोर्टल की परिकल्पना युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, प्रौद्योगिकी – संचालित सुविधाप्रदाता के रूप में की गयी है, जिसका लक्ष्य युवाओं को उनकी आकांक्षाएं पूरी करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने के लिए निष्पक्ष अवसर प्रदान करना है। यह एक 'फिजिटल प्लेटफॉर्म' (फिजिकल + डिजिटल) है, जिसमें वास्तविक गतिविधि के साथ – साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। वास्तविक गतिविधियों और डिजिटल कनेक्टिविटी का मिश्रण इस मंच की आधुनिक, गतिशील प्रकृति को दर्शाता है।

देश भर के नौजवान, माय भारत पोर्टल (https://www.mybharat.gov.in/) पर पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न अवसरों और आयोजनों के लिए साइन अप कर सकते हैं। माय भारत तेजी से युवा विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, जो पुलिस, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और विभिन्न मंत्रालयों के साथ विविध अवसरों, कार्यक्रमों और स्वयंसेवी गतिविधियों की पेशकश करता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी 2024 को पूरे भारत में 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने यात्रियों के लिए बेहतर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए यातायात पुलिस के साथ काम किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जनवरी 2024 को एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवकों से बातचीत में माय भारत की सफलता का उल्लेख करते हुए, पोर्टल को इतने कम समय में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने इस मंच की तीव्र और प्रभावशाली पहुंच को रेखांकित करते हुए कहा कि यह भारत की द्वीसवह सदी के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मंच है।

भविष्य में माय भारत का लक्ष्य अपने प्रभाव को और व्यापक बनाने के लिए नई सुविधाओं व पहलों की शुरुआत करना है। यह मंच उभरते क्षेत्रों में अपनी पहुंच को व्यापक बनाने तथा शैक्षणिक संस्थानों और युवा संगठनों के साथ अपनी सहभागिता को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। माय भारत अपने विकास का सिलसिला जारी रखते हुए युवाओं के बीच समान अवसर प्रदान करने और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा युवा भारत का लक्ष्य मौजूदा कार्यक्रमों को एकीकृत करके, उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करके दक्षता बढ़ाना है। यह सिर्फ एक संगठन भर नहीं, अपितु वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने का विजन है।

# वर्ष 2024–25 के लिए 9990 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित:मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री ने की विधायक प्राथमिकता बैठकों की अध्यक्षता

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। प्रथम दिन के पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर तथा सिरमौर के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2024-25 का आकार 9989.49 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

**जिला ऊना**

ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने उनके चुनाव क्षेत्र में पुराने कार्यो को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान विधायक निधि के नियमों में बदलाव कर रिटेनिंग वॉल आदि के लिए प्रभावितों को धन देने का प्रावधान किया है जिसे जून, 2024 से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्य शर्मा ने दौलतपुर चौक महाविद्यालय और स्कूल को अलग-अलग परिसर में स्थापित करने तथा उनके क्षेत्र में नशा माफिया पर लगाम कसने की मांग की।

कुटलैहड़ क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुट्टो ने खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने तथा खेल संघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने बेसहारा पशुओं को सहारा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया।

**जिला हमीरपुर**

भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने सीर खड्ड का तटीयकरण करने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया तथा भोरंज स्कूल में बहु-उद्देशीय हॉल बनाने की मांग की।

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा ने हमीरपुर में नए बस अड्डे के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने हमीरपुर में पॉलीक्लीनिक खोलने तथा जिला मुख्यालय में नया मिनी सचिवालय खोलने की मांग की।

बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की। उन्होंने विद्युत आपूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने और सड़कों के साथ उचित निकासी की व्यवस्था करने तथा बिझड़ी में पुलिस थाना खोलने का आग्रह किया।

**जिला सिरमौर**

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप ने क्षेत्र में जल शक्ति मण्डल खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिरगुल तथा भूरेश्वर मंदिर के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मांग की। उन्होंने सराहां-चंडीगढ़ सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र बनाने की मांग की।

नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने क्षेत्र के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये की घोषणाएं करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने डॉ. यशवन्त सिंह परमार चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा नर्सो के पदों को भरने की मांग की। उन्होंने भूमिहीनों को गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की।

पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुख राम चौधरी ने कहा कि यमुना नदी की हिमाचल की सीमा तय करने की मांग की, ताकि वहां पर अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को टयूबवेल चलाने के लिए बिजली के लंबित कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने की मांग की और पांवटा साहिब में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का भी आग्रह किया।

द्वितीय सत्र में जिला सोलन, चम्बा, बिलासपुर और लाहौल-स्पिति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं।

**जिला सोलन**

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक के.एल. ठाकुर ने सीमावर्ती क्षेत्र में नशा माफिया तथा खनन माफिया पर नकेल कसने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदा के दौरान राज्य सरकार के बेहतर कार्य की सराहना भी की। उन्होंने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त दभोटा पुल का दोबारा निर्माण जल्द करने का आग्रह किया।

कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने परवाणु व कामली औद्योगिक क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ने, टकसाल रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर बनाने तथा कौशल्या बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने की मांग की। उन्होंने शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर थीम आधारित ट्रेन चलाने का मामला रेलवे के साथ उठाने का भी आग्रह किया।

**जिला चंबा**

चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. हंसराज ने शिमला में आबादी का दबाव कम करने के लिए कुछ विभागों के कार्यालय प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने चुराह क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापित घराट मालिकों का पुनर्वास करने तथा उनके परिवार के सदस्यों को स्थाई नौकरी प्रदान करने की मांग की।

भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ जनक राज ने क्षेत्र में एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा का आयोजन जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक होता है, जिसे आगे पांच दिन और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इससे स्थानीय निवासियों को भी रोजगार मिल सके। उन्होंने भरमौर में वूल फेडरेशन का कार्यालय खोलने की भी मांग की।

चम्बा के विधायक नीरज नैय्यर ने चंबा-चुवाड़ी सुरंग बनाने का मांग की। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के लिए 165 करोड़ रुपये तथा चंबा में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये प्रदान करने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चंबा शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का भी आग्रह किया।

डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डी.एस. ठाकुर ने अपने चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरने की मांग की। उन्होंने पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए धन मुहैया करवाने, सलूणी से टांडा के लिए बस सेवा आरंभ करने तथा डलहौजी में नया बस अड्डा बनाने की मांग की।

**बिलासपुर**

झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीत राम कटवाल ने अपने चुनाव क्षेत्र में लंबित तीन पुलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तलाई और सिविल अस्पताल बरठीं के लिए पर्याप्त धनराशि तथा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान करने की मांग की।

बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने की मांग की। उन्होंने नशे की समस्या को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान आरम्भ करने का आग्रह किया।

श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने एफसीए तथा एफआरए के मामलों में तेजी लाने की मांग की ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने जल शक्ति विभाग में फील्ड स्टाफ के पद भरने तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए स्वारघाट-बिलासपुर के पुराने बस रूट पर सेवा आरम्भ करने की मांग की।

**जिला लाहौल-स्पिति**

लाहौल-स्पिति विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर ने जिला स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के समावेश की मांग की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती और विपणन करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने जिला लाहौल-स्पिति में शांति स्तूपों की मरम्मत करने की मांग की ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की।

**जिला कांगड़ा**

नूरपुर से विधायक रणबीर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तारीकरण का आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र खुखलेड़ के निर्माण तथा सदवां उप- तहसील के नए भवन के निर्माण, भूमि-कटाव रोकने के लिए चक्की और जबर खड्ड में चैनलाइजेशन का आग्रह किया। उन्होंने नशा माफिया पर लगाम लगाने पर भी सुझाव दिए।

इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन ने अपने चुनाव क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने, बसंतपुर स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने तथा नए शिक्षण संस्थान खोलने की बजाय पुराने संस्थानों को सुदृढ़ करने का आग्रह किया। उन्होंने आईटीआई गंगथ में नए व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू करने, बहुतकनीकी कॉलेज खोलने तथा भदरोहा में पुलिस चौकी खोलने की मांग की। उन्होंने नशा तथा खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया ने निर्माणाधीन रे कॉलेज तथा संयुक्त कार्यालय भवन फतेहपुर के कार्य को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने फतेहपुर में विद्युत बोर्ड का वृत्त कार्यालय खोलने तथा शाह नहर की मरम्मत के लिए समुचित धनरशि उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया।

देहरा से विधायक होशियार सिंह ने क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा बेहतर वन प्रबंधन से आर्थिक संसाधन बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने इमारती लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करने तथा प्रदेश के मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर्ची के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने लगभग 7000 पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे को केंद्र सरकार से उठाने का आग्रह भी किया।

जसवां प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र में निर्माणाधीन पॉलीक्लीनिक का कार्य पूरा करने के लिये समुचित धन उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज जंडौर को शुरू करने तथा चुनौर औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया।

ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन ने मां ज्वालामुखी मंदिर का मास्टर प्लान बनाकर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत एकीकृत केंद्र तथा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर मल निकासी योजना तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या दूर करने तथा चंबी ग्राउंड के सुधार की मांग रखी। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए समुचित कैलेंडर बनाने का भी आग्रह किया।

**जिला कुल्लू**

मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली बाई-पास सड़क के कार्य में तेजी लाने आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार से रोहतांग क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने, नए रोपवे लगाने तथा पर्यटन ग्राम विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर बनाने का भी आग्रह किया।

बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने एनएच-305 के सुदृढ़ीकरण की मांग की, ताकि पर्यटकों को तीर्थन घाटी तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने पेयजल तथा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन दलासनी पुल तथा बंजार बाईपास का कार्य जल्द पूरा करने का आग्रह किया।

आनी से विधायक लोकेंद्र कुमार ने सैंज-आनी सड़क के सुधारीकरण तथा श्रीखंड यात्रा को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। साथ ही नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने, आनी में पुलिस का ट्रैफिक विंग तथा सीए स्टोर खोलने की तथा जलोड़ी पास से सरयोलसर झील तक ई-व्हीकल चलाने का भी आग्रह किया।

दूसरे दिन अन्तिम सत्र में जिला शिमला तथा मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।

**जिला शिमला**

चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने नेरवा बस डिपो शुरू करने तथा जल शक्ति विभाग के कार्यो में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने चौपाल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, छैला-चौपाल सड़क के सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने तथा स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने का आग्रह किया।

ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने आपदा के दौरान बेहतर कार्यो के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने, ठियोग अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा देने व इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने तथा नारकंडा-हाटू रोपवे स्थापित करने की मांग की।

रामपुर से विधायक नंद लाल ने रामपुर में बाईपास सड़क के सुचारू संचालन के लिए पुल निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर रामपुर, ननखड़ी महाविद्यालय तथा सीए स्टोर दत्त नगर के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा ज्यूरी में महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया। उन्होंने आपदा के कारण विभिन्न गांवों में भू-धंसाव से प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए उचित स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाने की भी मांग की।

**जिला मंडी**

करसोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीप राज ने अपने चुनाव क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर करने तथा सेब उत्पादक क्षेत्रों में आपदा प्रभावित सड़कों को सुधारने का आग्रह किया। उन्होंने तत्तापानी से करसोग सड़क पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने तथा करसोग में पार्किंग का निर्माण करने की मांग की। उन्होंने तत्तापानी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया।

नाचन से विधायक विनोद कुमार ने अपने चुनाव क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया। उन्होंने बस अड्डा गोहर तथा चैलचौक के निर्माण के लिए वन स्वीकृतियां शीघ्र करवाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में प्रस्तावित दो किसान भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने तथा चैलचौक-पंडोह सड़क का जीर्णोद्धार करने की मांग भी की।

बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कल्खर से रत्ती सड़क को सुदृढ़ करने की मांग करते हुए रिवाल्सर झील सहित क्षेत्र की तीन झीलों का विस्तारीकरण तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप ठाकुर ने सरकाघाट अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क सुविधा के सुदृढ़ीकरण तथा सरकाघाट के अलावा एक अन्य मिनी सचिवालय बनाने की मांग की।

# कृषि और संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34490 करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता योजना तैयार:मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्त वर्ष 2024 – 25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024 – 25 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34490 करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर – 2024 – 25' भी जारी किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लोगों के सामजिक – आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना व स्टार्टअप इत्यादि अनेक कल्याण योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने बैंको से आग्रह किया कि इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए ऋण देने में अपना सक्रिय सहयोग दें ताकि किसान, बागवान तथा युवा इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रवाह पर जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदेश का कोई भी जिला 'क्रेडिट की कमी' जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इन जिलों में ऋण प्रवाह सामान्य है परन्तु प्रदेश का ऋण व जमा अनुपात 36:39 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल – स्पीति व चम्बा में ऋण व जमा अनुपात लगातार 40 प्रतिशत से कम है जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने बैंकों एवं अन्य हितधारकों को इन जिलों में ऋण व जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश ने नाबार्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हितधारकों को सम्मानित किया।

नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉ. विवेक पठानिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और डीजीएम मनोहर लाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

# मुख्यमंत्री ने की कांग्रेस युवा संवाद कार्यक्रम की सराहना

**शिमला/शैल।** कांग्रेस युवा संवाद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस युवा संवाद कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस विचारधारा से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहला युवा कांग्रेस संवाद कार्यक्रम बिलासपुर जिला से 17 दिसम्बर, 2023 को आरम्भ हुआ तथा प्रत्येक जिला में यह कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इन कार्यक्रमों के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान राज्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याण नीतियों को अधिक से अधिक प्रसारित करने का आग्रह किया ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित न रहे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन बहाल की गई, अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख – आश्रय योजना तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में 21000 नौकरियां घोषित की गई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज पर निर्भरता कम कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है तथा एक वर्ष में अर्थ व्यवस्था में 20 प्रतिशत सुधार आया है।

इस अवसर पर प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट, कांग्रेस युवा संवाद से जुड़े मस्त राम, रवि रतन शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

# सात हजार एकल तथा विधवा नारियों को गृह निर्माण को मिलेगा अनुदान: बाली

**शिमला/शैल।** पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैक आरएस बाली ने कहा कि राज्य सरकार चालू वित वर्ष में सात हजार विधवा तथा एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए डेढ़ – डेढ़ लाख रूपये का अनुदान देगी ताकि महिला सशद्रिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकें। बाली ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार के जोड़ने के लिए भी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सृ ढ़ किया जाएगा तथा महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए उचित कदम भी उठाए जाएंगे ताकि स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे इस के लिए यूनिटी मॉल भी स्थापित किया जाएगा इसके साथ ही अपना कांगड़ा ऐप के माध्यम से भी उत्पादों को विक्रय करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। बाली ने कहा कि महिला सशद्रिकरण की दिशा में प्रगाढ़ता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु के कुशल नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा सरकार द्वारा अनेको जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका सीधा लाभ लोगों को प्राप्त होता है।

# शिवरात्रि तक पूरा करें पंचवक्र फुट ब्रिज का काम:विक्रमादित्य सिंह

**शिमला/शैल।** लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचवक्र फुटब्रिज का काम शिवरात्रि तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मंडी के अपने दौरे में निर्माणाधीन फुट ब्रिज के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को युद्धस्तर पर काम करने को कहा। इस दौरान सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी साथ रहीं।

बीते मानसून ब्यास नदी में आयी बाढ़ में पंचवक्र महादेव मंदिर का फुटब्रिज ध्वस्त हो गया था। सांसद प्रतिभा सिंह ने इसके पुनर्निर्माण कार्य के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपये प्रदान किए थे। उनके प्रयासों से इस कार्य के लिए सरकार ने अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई है।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल में आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गो और उनके साथ लगती अन्य सड़कों के सुधार के लिए शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए 152 करोड़ रुपये जारी करने का भरोसा दिया है। आशा है अगले दो – तीन दिन में यह धनराशि विभाग को प्राप्त हो जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस धनराशि से प्रदेश की अन्य सड़कों के साथ साथ मंडी – कुल्लू को जोड़ने वाली दो वैकल्पिक सड़कों चैलचौक – पंडोह और कमांद – कटिंडी – कटौला – बजौरा के सुधार और विस्तार का काम भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कमांद – कटौला – बजौरा और चैलचौक – पंडोह सड़क का विस्तारीकरण कर इन मार्गो को कुल्लू – लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

# कर्मचारियों के वित्तीय भुगतान के मामलो में जयराम ने अपनाई दोहरी नीति:महासंध

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाऐं महासंघ ने पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के उन व्यक्तव्यों को उनके घड़ियाली आँसू और उनकी ओछी राजनीतिक चाल बताया है जिसमे वह कर्मचारियों के वेतन और डी ए न मिलने पर आज सार्वजनिक रूप से ब्यानबाजी कर रहे है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार कार्यकारी अध्यक्ष गोविन्द सिंह बरागटा अतिरिक्त महासचिव विनोद शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण मेहता सचिव शीला चदेल ने अपने संयुक्त ब्यान मे कहा है कि पूर्व मुख्य मंत्री कर्मचारी मसलो पर आज जो ब्यानबाजी कर रहे है वह उनका कर्मचारी वर्ग को बरगलाने का असफ़ल प्रयास है जबकि सच्चाई यह है की आज कर्मचारियो के जो वित्तीय मसले और देनदारियां लम्बित है, वह आज तक उनके अकुशल और लूंज – पूंज रहे नेतृत्व के कारण ही हो रहा है, यदि उन्होने अपने कार्यकाल में समय रहते कर्मचारियो के संशोधित वेतनमान ऐरियर, डी ए और अन्य मामलो के निपटारे की व्यवस्था की होती तो आज कर्मचारी वर्ग को यह दिन नही देखने पडते, लेकिन जयराम ठाकुर की सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन और राजस्व घाटे को कम करने की दिशा मे काम करने की बजाये उल्टे अस्सी हजार करोड का कर्जा प्रदेश पर खड़ा कर दिया जो आज प्रदेश के हर वर्ग के लिए नासूर बन हुआ है।

महासंघ के नेताओ ने कहा कि कर्मचारियों के वित्तीय भुगतान के मामलो मे दोहरी नीति पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने ही अपनाई है जिसको लेकर आज 2022 से पहले के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी सरकार को ज्ञापन दे रहे है, यही नही डी ए की किस्तों के भुगतान मे भी जयराम ठाकुर ने भारत सरकार के मानको से छेडछाड कर 11% की जगह 6% डी ए देकर कर्मचारियो का 5% डी ए रफा – दफा ही कर दिया जबकि ऐसा पहले कभी नही हुआ, लेकिन उस समय पूर्व मुख्यमन्त्री ने कर्मचारी वर्ग की आवाज को सुनने की बजाये उन्हे अंगूठा दिखाया तो फिर आज यह दिखावे के आँसू किस लिये है।

पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर आज भी अपने उन चेहतो के तबादला समायोजन की वर्तमान सरकार से गुहार लगाते रहते है जिनके साथ मिलकर उन्होने कर्मचारियो के बहुमत से चुनी संवैधानिक कार्यकारिणी को दरकिनार कर क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार फैलाने वालो को जबरन कर्मचारियो पर थोपने का राजनीतिक षडयंत्र रचकर चुने हुये ईमानदार कर्मचारी संगठन के नेताओ को प्रताड़ित करते रहे। महासंघ के नेताओ ने कहा है कि पूर्व मे हर सरकार मे फलते फूलते रहे तबादला उघोग पर आज जिस तरह से रोक लगी है वह ऐतिहासिक है और यह मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की राजनीतिक दृढ़ ईच्छाशक्ति से ही सम्भव हुआ है इससे सरकारी कार्यालयो का महौल बहुत सुधरा है मुकद्दमेबाजी भी काफी कम हुई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

# क्या चण्डीगढ़ के घटनाक्रम ने रोकी हिमाचल के भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा

**शिमला/शैल।** प्रदेश भाजपा 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव में यहां की चारों सीटों पर जीत हासिल करती रही है। मण्डी में जब पण्डित राम स्वरुप के निधन के कारण उपचुनाव हुआ तब यहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह विजयी हुई। जबकि मण्डी जयराम ठाकुर का गृहक्षेत्र था और वह सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। 2019 के चुनावों के बाद यदि हिमाचल के सांसदो की प्रदेश में सक्रियता का आकलन करें और यह देखें कि किसकी क्या उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर रही है तो शायद उल्लेखनीय कुछ भी नहीं मिले। क्योंकि 2019 के बाद देश में भाजपा की पहचान केवल मोदी ही बन चुके हैं। आज भी मोदी के बिना भाजपा नहीं है कि स्थिति है। 2017 में प्रदेश में भी भाजपा की सरकार मोदी के नाम पर बनी थी। लेकिन

2022 के चुनाव आने तक प्रदेश की जयराम सरकार मोदी-शाह के भरपूर प्रयास के बावजूद सता में वापसी नहीं कर पायी। भाजपा प्रदेश में वापसी क्यों नहीं कर पायी जबकि लोकसभा की चारों सीटें उसके पास थी। यह हार एक प्रतिशत से भी कम अन्तर से हुई है। और इस हार के कारणों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। जय राम सरकार के वक्त भाजपा सांसदों कि क्या स्थिति थी यह प्रदेश का हर आदमी जानता है। जबकि जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अनुराग ठाकुर वरिष्ठ मंत्री थे। लेकिन इसके बावजूद भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी। यह चर्चा आज इसलिये प्रसांगिक हो जाती है क्योंकि भाजपा लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं कर पायी है। पिछले दिनों जब यह चर्चा उठी की नड्डा प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं उसके बाद से पार्टी के भीतरी हल्कों में इसको लेकर दबी जुबान से यह चर्चा गंभीर हो गई है। नड्डा के प्रदेश दौरों से इन चर्चाओं को और बल मिलता जा रहा है। इन चर्चाओं का आधार यह माना जा रहा है कि नड्डा की राज्यसभा टर्म खत्म हो गई है और उनको दूसरी टर्म पार्टी के नियमानुसार मिलना संभव नहीं माना जा रहा है। यह स्थिति राष्ट्रीय अध्यक्षता से लेकर है। ऐसे में नड्डा को सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिये लोकसभा चुनाव लड़ना एक आसान विकल्प माना जा रहा है। नड्डा के लोस प्रत्याशी बनने की सूरत में अनुराग ठाकुर को चण्डीगढ़ शिफ्ट किये जाने की संभावना बनती जा रही है। क्योंकि पूरे देश में चुनाव तो मोदी के नाम से ही लड़ा जाना है। लेकिन चण्डीगढ में मेयर के चुनाव में जो कुछ घटा है और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से उसका संज्ञान लिया है उसके बाद परिदृश्य कुछ बदलता नजर आ रहा है। चण्डीगढ़ के इस परिदृश्य में हिमाचल के लोस उम्मीदवारों की घोषणा में देरी बर्तने का रास्ता लिया गया है।

# शिक्षक वर्ग में बढ़ता रोष सरकार के लिए घातक होगा

**शिमला/शैल।** प्रदेश के एमसी शिक्षक हड़ताल पर है। ऐसे मौसम में भी शिमला में धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाये। नवम्बर में जेबीटी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिये कॉउंसलिंग हुई थी। इसके तहत 1161 पद भरे जाने थे। प्रदेश में जेबीटी के 4000 पद खाली हैं। लेकिन नवम्बर में हुई इस काउंसलिंग के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुये हैं। अब इस वर्ग में भी रोष व्याप्त हो गया है। यह लोग भी सड़क पर आने के लिये बाध्य हो रहे हैं। शास्त्री अपना रोष व्यक्त करते हुये विरोध मार्च निकाल चुके हैं। एसएमसी के करीब 2550 अध्यापक प्रदेश में कार्यरत हैं। धूमल के शासनकाल में एसएमसी के माध्यम से यह लोग भर्ती किये थे। एसडीएम और स्कूल के प्रधानाचार्य इसका साक्षात्कार लेने वालों में शामिल रहे हैं। धूमल के बाद वीरभद्र और जयराम की सरकारें भी आकर चली गयी। लेकिन किसी ने भी इनको नियमित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। सुक्खु सरकार आने के बाद इनके मामले सुलझाने के लिये तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर उनसे तीन माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। लेकिन सरकार को 13 माह बाद भी इस

कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली है क्योंकि कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हो पायी है। क्या मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना ऐसा हो सकता है।

स्मरणीय है कि सुक्खु सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी हासिल करने के लिए एक तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में कर्मचारियों के 70000 पद खाली हैं । इनमें अकेले शिक्षा विभाग में ही बीस हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों के मामले हर सरकार में उच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं और अदालत ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुये प्रशासन की निंदा भी की है। कई जगह तो अभिभावकों ने स्कूलों पर ताले तक भी लगा दिये हैं। जयराम सरकार के दौरान मण्डी में हीऐसा घट चुका है। स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षण अभी भी शायद आउटसोर्स के माध्यम से ही चल रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षकों और ड्राइवर के पद खाली रहने का संबद्ध समाज पर गंभीर असर पड़ता है। आज शिक्षा विभाग में गेस्ट शिक्षकों की भर्ती की योजना बनाई जा रही है। क्योंकि शिक्षकों की कमी है। इसी कमी के कारण एसएमसी शिक्षक भर्ती किये गये थे। जो आज आन्दोलन के लिये विवश हो गये हैं। कल को यह गैस्ट शिक्षक भी इसी मुकाम पर पहुंच जायेंगे। सरकार नियमित भर्तियां इसलिये टालती जा रही हैं क्योंकि उसके पास धन का अभाव है। लेकिन दूसरी और भाजपा शासन में अटल आदर्श विद्यालय खोले गये थे और आज उसी तर्ज में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल घोषित किया जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की योजना है। इन स्कूलों को बनाने में ही करोड़ों का खर्च हो जायेगा और उससे लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल पायेगा। जबकि इसी खर्च के साथ स्कूलों की वर्तमान दशा को सुधारा जा सकता है। शिक्षकों के सारे खाली पदों को भरा जा सकता है। लेकिन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और अटल आदर्श विद्यालय खोलकर अपने-अपने आकांओं को तो खुश किया जा सकता है परन्तु उससे स्कूलों की वर्तमान दशा को नही सुधारा जा सकता। इस दशा को सुधारने के लिये आम आदमी के नजरिये से सोचने की आवश्यकता है। आज एसएमसी शिक्षक धरने पर हैं और कोई भी उनसे बात करने का साहस नहीं कर पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसका आकार क्या रूप ले लेगा उसकी और कोई भी सोच नहीं पा रहा है। जबकि हर गांव इससे प्रभावित हो रहा है।